श्रीराम एवं अन्य

बनाम

बम्बई राज्य

05 दिसम्बर, 1960

[जफ़र इमाम, के. सुब्बाराव और रघुबर दयाल, जे.जे.]

आपराधिक मुकदमा- सुपुर्दगी- क्या किसी साक्ष्य को रिकॉर्ड किए बिना की जा सकती है- सुपुर्द करने वाले न्यायालय का कर्तव्य- दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (V/1898), धारा 207-ए

जांच के लिए तय की गई तारीख पर अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उसका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी भी गवाह से पूछताछ करने का इरादा नहीं है। मजिस्ट्रेट ने यह विचार करने के लिए जांच स्थगित कर दी कि क्या सुपुर्दगी से पहले कोई सबूत दर्ज करना आवश्यक था। स्थगित तिथि पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि किसी भी गवाह से पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए और उन्हें सत्र न्यायालय को सौंप दिया। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207-ए की उप-धारा (4) के तहत गवाहों की जांच किए बिना उन्हें सत्र को सौंपने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अभिनिर्धारित किया गया कि सुपुर्दगी का आदेश वैध था और मजिस्ट्रेट के पास कोई साक्ष्य दर्ज किए बिना यह आदेश देने का अधिकार क्षेत्र था। संहिता की धारा 207-ए के तहत स्थिति इस प्रकार है:

(i) मजिस्ट्रेट केवल ऐसे चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य लेने के लिए बाध्य है जो वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा कमिटिंग कोर्ट के समक्ष पेश किए गए हैं;

(ii) यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि साक्ष्य लेना न्याय के हित में है, चाहे वह चश्मदीद गवाहों का हो या दूसरों का, तो ऐसा करना उसका कर्तव्य है;

(iii) यदि मजिस्ट्रेट की राय यह नहीं है और यदि अभियोजन पक्ष ने किसी भी चश्मदीद गवाह की जांच नहीं की है, तो उसके पास संहिता की धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को रिहा करने या सुपुर्द करने का अधिकार क्षेत्र है;

(iv) मजिस्ट्रेट का विवेक एक न्यायिक विवेक है जिसे उच्चतर न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है।

माचेरला हनुमंत राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [1958] एस.सी.आर. 396, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 57 और 58/1960

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर की आपराधिक अपील संख्या 94/1958 में द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 5/6 नवंबर, 1958 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

आपराधिक अपील संख्या 57/1960 में अपीलकर्ता की ओर से जय गोपाल सेठी और जी.सी.माथुर।

आपराधिक अपील संख्या 58/1960 में अपीलकर्ता की ओर से जी. सी. माथुर।

प्रतिवादी की ओर से गोपाल सिंह और डी. गुप्ता।

5 दिसंबर, 1960। न्यायालय का फैसला सुब्बा राव, जे. द्वारा सुनाया गया-

ये दोनों अपीलें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा 207 ए के प्रावधानों की व्याख्या पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। जिन तथ्यों ने इन अपीलों को जन्म दिया है उन्हें संक्षेप में बताया जा सकता है। ये अपीलें 29 नवंबर, 1957 को हुई एक घटना से संबंधित हैं, जब निमगांव गांव में एक सदाशिव नामक व्यक्ति की उसके घर के आंगन में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि चार अपीलकर्ता लाठियों से लैस होकर मृतक के घर गए, उसे घर से बाहर खींच लिया और आंगन में लाठियों से पीटा; और पिटाई के परिणामस्वरूप अगले दिन शाम लगभग 5 बजे भंडारा अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। जांच के बाद, पुलिस ने संबंधित दस्तावेजों के साथ संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने अपीलकर्ताओं को धारा 173 की उपधारा (1) के तहत अग्रेषित रिपोर्ट की एक प्रति, धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेज या उसके प्रासंगिक उद्धरण दिए, जिस पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा करने का प्रस्ताव रखा जिसमे धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए बयान भी शामिल थे और उन्हें उन व्यक्तियों के बारे में भी सूचित किया जिन्हें अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों के रूप में जांचने का प्रस्ताव दिया था। मजिस्ट्रेट ने मामले को 10 फरवरी, 1958 को जांच के लिए पोस्ट किया और उस तारीख को अभियोजन पक्ष ने सूचित किया कि उसका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी भी गवाह से पूछताछ करने का इरादा नहीं है। अपीलकर्ताओं की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।

लेकिन मजिस्ट्रेट ने जांच 12 फरवरी, 1958 तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि वह इस बात पर विचार करना चाहते थे कि सुपुर्दगी से पहले कोई सबूत दर्ज किया जाना आवश्यक है या नहीं। 12 फरवरी, 1958 को उन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि उस स्तर पर किसी भी गवाह से पूछताछ की आवश्यकता नहीं है; इसके बाद, उन्होंने आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 448 के तहत आरोप तय किए और अपीलकर्ताओं को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष ने चार प्रकार के साक्ष्य पेश किए (1) चश्मदीद गवाह, अर्थात्, पीडब्लू 6, 11, 20 और 25; (2) पीडब्लू 18, 22 और 19 द्वारा समर्थित मृत्युकालिक कथन, प्रदर्श पी-15; (3) पीडब्लू 20 और 25 द्वारा जेल में अपीलकर्ताओं की पहचान; और (4) अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी। बचाव पक्ष ने चार गवाहों से पूछताछ की। संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से सही साबित हुआ है और चारों अपीलकर्ताओं ने मृतक के घर में प्रवेश किया और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताए गए तरीके से उसे पीटा। चूंकि मृतक के शरीर पर कम से कम 12 चोट के निशान मिले थे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े में चोट आई, और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि मौत सदमे और उक्त फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप रक्तस्राव के कारण हुई थी, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपी-अपीलकर्ता हत्या के दोषी थे और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया, और उन्होंने आगे उन्हें मृतक के घर में प्रवेश करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया। इन निष्कर्षों पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को पहले मामले में आजीवन कारावास और दूसरे मामले में 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपीलकर्ताओं ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के

खिलाफ नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने सम्पूर्ण साक्ष्यों का पुनः सर्वेक्षण करने पर विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत होकर अभियोजन पक्ष को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता केवल भारतीय दंड संहिता धारा 304, भाग I, सपठित धारा 34 के तहत दोषी थे; और परिणामस्वरूप उन्होंने अपीलकर्ता 1 के संबंध में सज़ा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल के कठोर कारावास और अपीलकर्ता 2 से 4 के संबंध में 7 साल के कठोर कारावास कर दिया। उक्त दोषसिद्धि और सजाओं के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति द्वारा, इस न्यायालय में अपील की है। प्रथम अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक अपील संख्या 57/1960 दायर की गई है और अपीलकर्ता 2 से 4 द्वारा आपराधिक अपील संख्या 58/1960 दायर की गई है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष निम्नलिखित दो बिंदु उठाए: (1) सत्र न्यायालय और, अपील पर, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में सबूतों और मामले की परिस्थितियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है कि अपीलकर्ताओं ने अपराध किया था। (2) सत्र न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं का विचारण और दोषसिद्धि शून्य थी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 207 ए की उपधारा (4) के तहत गवाहों की जांच किए बिना अपीलकर्ताओं को सत्र न्यायालय को सौंपने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और चूँकि सुपुर्दगी का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था, दोष को संहिता की धारा 532 या धारा 537 के तहत ठीक नहीं किया गया।

पहला प्रश्न किसी भी विचार के योग्य नहीं है। दोनों निचली अदालतों ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा पेश किए गए सबूतों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथ्यात्मक प्रश्नों पर हस्तक्षेप न करना इस

न्यायालय की सुस्थापित प्रथा है, विशेष रूप से जब वे समवर्ती निष्कर्ष हों। हमें इस मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं मिली। इसलिए, हम पहले तर्क को अस्वीकार करते हैं।

दूसरा विवाद संहिता की धारा 207 ए के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या पर आधारित है। धारा के प्रासंगिक प्रावधानों को समझने का प्रयास करने से पहले उक्त धारा के इतिहास पर संक्षेप में ध्यान देना उपयुक्त होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जैसा कि यह मूल रूप से था, सुपुर्दगी की कार्यवाही के मामले में पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई कार्यवाही और पुलिस रिपोर्ट के अलावा शुरू की गई अन्य कार्यवाही के बीच कोई अंतर नहीं था। सुपुर्दगी की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य उस मामले का पता लगाने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए जांच करना था जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय के समक्ष की जानी थी। यह मुख्य रूप से एक अभियुक्त को सत्र न्यायालय में उसके खिलाफ पेश किए जाने वाले सबूतों के विवरण को पहले से जानने का अवसर देना था ताकि वह अपना बचाव तैयार करने की स्थिति में हो सके। एक अन्य उद्देश्य, जो कम महत्वपूर्ण नहीं था, वह था मजिस्ट्रेट को किसी आरोपी को आरोपमुक्त करने में सक्षम बनाना, यदि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं था। इस प्रक्रिया से ऐसे अभियुक्तों का अनावश्यक उत्पीड़न रोका गया और साथ ही सत्र न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बचाया गया। व्यवहार में सुपुर्दगी की कार्यवाही, चाहे विधायिका द्वारा इरादा हो या नहीं, एक अन्य उद्देश्य की पूर्ति करती है, अर्थात्, इसने अभियुक्तों को गवाहों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने का अवसर दिया, ताकि सत्र न्यायालय में उनके साक्ष्य, संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए बयान और उनके द्वारा दिए गए सबूतों के बीच विसंगतियां सामने आ सकें। हालाँकि अक्सर आरोपी व्यक्तियों ने गवाहों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए इस अतिरिक्त अवसर का पूरा फायदा उठाया, और बहुत बार यह मुकदमों के दोहराव के रूप में सामने आया जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक मामलों

के निपटारे में देरी हुई। सुपुर्दगी की कार्यवाही का लाभ केवल अभियुक्तों के लिए नहीं था, बल्कि अभियोजन पक्ष के लिए भी गवाहों की जांच करके कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी गवाही को इस अर्थ में सुरक्षित किया गया था कि हालांकि बाद में इसमें छेड़छाड़ की गई थी- यह दुर्भाग्य से आपराधिक मामलों में एक निरंतर घटना है- यह संहिता की धारा 288 के तहत उक्त साक्ष्य को मूल साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकता है। विधायिका ने, अपने विवेक से, संभवतः सोचा कि सत्र मामलों के निपटान में अनुचित देरी विस्तृत और लंबी सुपुर्दगी वाली कार्यवाही के कारण थी और उस संबंध में संहिता में संशोधन करने के लिए कदम उठाया। संपूर्ण धारा 207ए को 1955 के अधिनियम XXVI द्वारा जोड़ा गया है। जहां धारा ने पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई सुपर्दगी कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया को सरल बना दिया, इसने मौजूदा प्रक्रिया को पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा शुरू की गई कार्यवाही तक सीमित कर दिया। मामलों के दो वर्गों के बीच इस अंतर का उचित तथ्यात्मक आधार था। पुलिस रिपोर्ट के मामले में, गहन जांच की गई होगी और जांच अधिकारी ने संहिता की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी होगी। संहिता की संशोधित धारा 173 पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह कर्तव्य भी सौंपती है कि वह मुकदमे से पहले, उस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट प्रतियाँ, धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके अन्य सभी दस्तावेज़ या प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान, यदि कोई हो, और धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए बयान और गवाहों की सूची जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है, शामिल है, आरोपियों को मुफ्त में प्रस्तुत करेगा। उक्त सामग्री पर पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई कार्यवाही में मजिस्ट्रेट आमतौर पर अभियोजन के मामले को समझने और पेश किए जाने वाले सबूतों की प्रकृति को जानने की स्थिति में होगा,

जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभियुक्त को यह भी पहले से जानने का अवसर मिलेगा कि उसे किस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उसके खिलाफ क्या सबूत पेश किए जाएंगे। लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से शुरू की गई कार्यवाही में, ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए ऐसे मामले पर पुरानी प्रक्रिया लागू होती रहेगी। आइए इस पृष्ठभूमि के साथ संहिता की धारा 207 ए के प्रावधानों को देखें। संहिता की धारा 207 ए के प्रासंगिक प्रावधानों को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:

> धारा 207 ए: (1) जब, पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को धारा 173 के तहत अग्रेषित रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो वह इस धारा के तहत जांच करने के उद्देश्य से, एक तारीख तय करेगा, जो रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कोई बाद की तारीख तय न करे।
>
> (2) यदि, ऐसी तारीख से पहले किसी भी समय, अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी किसी गवाह की उपस्थिति या किसी दस्तावेज़ या चीज़ को पेश करने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा जब तक कि, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, वह ऐसा करना अनावश्यक न समझे।
>
> (3) जांच के प्रारंभ में, मजिस्ट्रेट, जब आरोपी उपस्थित होता है या उसके सामने लाया जाता है, तो खुद को संतुष्ट करेगा कि धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेज आरोपी को प्रदान किए गए हैं और यदि उसे पता

चलता है कि अभियुक्त को ऐसे दस्तावेज़ या उनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो वह उसे इस प्रकार उपलब्ध कराएगा।

(4) इसके बाद मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, का साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध के वास्तविक कमीशन के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियोजन के लिए किसी एक या अधिक गवाहों का साक्ष्य लेना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसे साक्ष्य भी ले सकता है।

(5) अभियुक्त को उप-धारा (4) के तहत जांच किए गए गवाहों से जिरह करने की स्वतंत्रता होगी, और ऐसे मामले में, अभियोजक उनसे दोबारा पूछताछ कर सकता है।

(6) जब उपधारा (4) में निर्दिष्ट साक्ष्य ले लिया गया हो और मजिस्ट्रेट ने धारा 173 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर विचार कर लिया हो, और यदि आवश्यक हो, तो अभियुक्त से उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूछताछ कर ली हो और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया हो, तब ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय है कि ऐसे साक्ष्य और दस्तावेज़ आरोपी व्यक्ति को मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार नहीं बताते हैं, तो अपने कारणों को दर्ज करेगा और उसे आरोपमुक्त कर देगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत न हो कि ऐसे व्यक्ति पर उसके या किसी अन्य

मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में वह तदनुसार आगे बढ़ेगा।

(7) जब, ऐसे सबूत लिए जाने पर, ऐसे दस्तावेजों पर विचार किए जाने पर, ऐसी जांच (यदि कोई हो) किए जाने पर और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए जाने पर, मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त को मुकदमे के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, तो वह यह घोषित करते हुए एक आरोप विरचित करेगा कि अभियुक्त पर किस अपराध का आरोप लगाया गया है।

उप-धारा (4) की व्याख्या पर, जो वर्तमान मामले में जांच के अधीन मुख्य उप-धारा है, भारत में उच्च न्यायालयों ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। उक्त निर्णयों पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन यदि हम परस्पर विरोधी विचारों को बता दें तो यह पर्याप्त होगा, जो इस प्रकार हैं: (1) उपधारा (4) के तहत अभियोजन पक्ष पुलिस रिपोर्ट में बताए गए सभी चश्मदीद गवाहों की जांच करने के लिए बाध्य है और उक्त उपधारा के दूसरे भाग के तहत गवाहों की जांच करने का मजिस्ट्रेट का विवेक केवल चश्मदीद गवाहों के अलावा अन्य गवाहों के संबंध में है: एम. पवलप्पा बनाम मैसूर राज्य (ए.आई.आर. 1957 मैसूर 61), राज्य बनाम अनादि बेतनकर (ए.आई.आर. 1958 उड़ीसा 241), घीसा बनाम राज्य (ए.आई.आर. 1919 राज. 294) और चंदू सत्यनारायण राज्य (ए.आई.आर. 1959 ए.पी. 651) देखें। (2) उप-धारा (4) के पहले भाग के तहत चश्मदीद गवाहों की जांच करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति केवल ऐसे गवाहों तक ही सीमित है जो अभियोजन चलाने वाले अधिकारी द्वारा न्यायालय में पेश किए जाते हैं और यदि उसने ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया है तो उक्त उपधारा के दूसरे भाग के तहत मजिस्ट्रेट किसी भी चश्मदीद गवाह से पूछताछ

नहीं कर सकता है, क्योंकि, इस दृष्टिकोण के अनुसार, दूसरा भाग चश्मदीदों के अलावा केवल गवाहों से संबंधित है। (3) यदि अभियोजन पक्ष ने कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया है तो न्यायालय अपने विवेक से दूसरे भाग के तहत किसी भी गवाह की जांच नहीं कर सकता है, लेकिन संतुष्ट होने पर संहिता की धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को रिहा कर सकता है या सत्र को सुपुर्द कर सकता है राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (ए.आई.आर. 1960 237), यू.पी. राज्य बनाम सत्यवीर (ए.आई.आर. 1959 408) देखें। (4) पहला भाग मजिस्ट्रेट को पेश किए गए केवल चश्मदीद गवाहों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन दूसरा भाग उसे पेश किए गए गवाहों के अलावा किसी भी गवाह की जांच करने का अधिकार देता है, चाहे वह चश्मदीद गवाह हो या नहीं, और ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष किसी भी गवाह या किसी महत्वपूर्ण चश्मदीद को पेश करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा, यदि अदालत कम से कम महत्वपूर्ण गवाहों की जांच किए बिना संहिता की धारा 173 के तहत संदर्भित दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करती है तो अदालत अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं करेगी राज्य बनाम यासीन (ए.आई.आर. 1958 सभी. 861), इन रे पेड्डा अम्मा मुत्तिगडु (ए.आई.आर. 1959 ए.पी. 469), ए. इशाक बनाम राज्य (ए.आई.आर. 1958 कैल. 341) और माणिक चंद बनाम राज्य (ए.आई.आर. 1958 कैल. 324) देखें। हमने बार में उद्धृत उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया है और उठाए गए प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उनसे काफी सहायता प्राप्त की है। आइए अब हम इसके इरादे का पता लगाने के लिए संहिता की धारा 207 ए के प्रासंगिक प्रावधानों को देखें। साक्ष्य लेने की दृष्टि से उपधारा (4) सबसे महत्वपूर्ण धारा है। यह दो भागों में है, पहले भाग में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के परीक्षण का प्रावधान है और दूसरे भाग में अन्य गवाहों के परीक्षण का प्रावधान है। व्याख्या के मूलभूत नियमों में से एक यह है कि यदि किसी क़ानून के

शब्द अपने आप में सटीक और स्पष्ट हैं "उन शब्दों को उनके नैसर्गिक और सामान्य अर्थों में व्याख्या करने से अधिक आवश्यक नहीं है, ऐसे मामले में शब्द स्वयं विधायिका के इरादे को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करते हैं"। उप-खंड का पहला भाग इस प्रकार है: "तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा, यदि कोई हो, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध को करने के लिए के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।" शब्द "करेगा" मजिस्ट्रेट पर साक्ष्य लेने का अनिवार्य कर्तव्य लगाता है; लेकिन इसके बाद उक्त साक्ष्य की प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। खंड "जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध के वास्तविक कमीशन के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है" "ऐसे व्यक्तियों" शब्दों को नियंत्रित करता है; इसका परिणाम यह हुआ कि साक्ष्य लेने का मजिस्ट्रेट का कर्तव्य केवल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों तक ही सीमित है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष को चश्मदीद गवाहों को सुपुर्द किए जाने वाले न्यायालय को सुपुर्द करने की अनुमति देना विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है और इसलिए "प्रस्तुत" शब्द को "उद्धृत" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस व्याख्या को स्वीकार करने का अर्थ है "प्रस्तुत" शब्द के स्थान पर "उद्धृत" शब्द रखना: ऐसा निर्माण स्वीकार्य नहीं है, खासकर, जब विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्द का स्पष्ट अर्थ साफ और स्पष्ट हो, और उस अर्थ की स्वीकृति से यह खंड निरर्थक नहीं हो जाता। "ऐसे व्यक्तियों" शब्दों और उपरोक्त खंड के बीच "यदि कोई हो" वाक्यांश इस बात पर जोर देता है कि अभियोजन पक्ष ऐसे किसी भी व्यक्ति को पेश नहीं कर सकता है, ऐसे में ऐसे गवाहों की जांच करने की बाध्यता उत्पन्न नहीं हो सकती है। उपधारा के दूसरे भाग की शब्दावली भी बिना किसी अस्पष्टता के है और इसमें लिखा है: "और यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियोजन के लिए किसी एक या अधिक गवाहों का साक्ष्य लेना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसे साक्ष्य भी ले सकता है।" इसमें कोई

संदेह नहीं है कि "वह साक्ष्य ले सकता है" खंड में "हो सकता है" शब्द मजिस्ट्रेट पर अन्य साक्ष्य लेने का कर्तव्य लगाता है; लेकिन वह कर्तव्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसकी राय हो कि साक्ष्य लेना न्याय के हित में आवश्यक है। कर्तव्य को जन्म देने वाली शर्त की पूर्ति मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दी गई है। साक्ष्य लेने का कर्तव्य तभी उत्पन्न होता है जब वह अपेक्षित राय रखता हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विवेक न्यायिक है, इसका प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा यथोचित रूप से किया जाना चाहिए। यदि वह इसका गलत तरीके से प्रयोग करता है, तो इसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो "अन्य गवाह" शब्दों का क्या अर्थ है? क्या उनका मतलब चश्मदीद गवाहों के अलावा अन्य गवाहों से है या अभियोजन पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए गवाहों के अलावा, चश्मदीद गवाह से हैं या नहीं? अभियोजन पक्ष के मामले में गवाही देने वाले गवाह अलग-अलग श्रेणियों के हो सकते हैं, अर्थात्, (i) ऐसे गवाह जो कथित अपराध के वास्तविक कमीशन के चश्मदीद गवाह हैं; (ii) गवाह जो ऐसे तथ्य बताते हैं जो अपराध करने का मकसद बताते हैं; (iii) गवाह जो जांच और परीक्षण से सामने आए तथ्यों के बारे में बात करते हैं; और (iv) गवाह जो अपराध होने की संभावना की परिस्थितियों और तथ्यों के बारे में बात करते हैं, जिसे तकनीकी रूप से ठोस साक्ष्य के रूप में वर्णित किया गया है। उपधारा (4) मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की पहली श्रेणी की जांच करने का कर्तव्य देती है। "वास्तविक" शब्द "कमीशन" शब्द को अर्हता प्रदान करता है, इस तथ्य पर जोर देता है कि उक्त गवाह वे होने चाहिए जिन्होंने अपराध होते देखा है। हमने पहले भाग की व्याख्या करते समय यह माना है कि मजिस्ट्रेट को केवल उन्हीं गवाहों की जांच करनी चाहिए जो अभियोजन पक्ष द्वारा उसके सामने पेश किए गए हैं; लेकिन हो सकता है कि किसी मामले में चश्मदीद गवाह न हों, या अगर हों तो अभियोजन पक्ष ने उन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया हो। उप-धारा का

दूसरा भाग इसलिए मजिस्ट्रेट को सभी श्रेणियों के किसी एक या अधिक गवाहों की जांच करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसमें वे चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त उपधारा के पहले भाग के अर्थ के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उप-धारा (6) और (7) इंगित करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य लेना दोषमुक्त करने या सुपुर्दगी का आदेश देने के लिए एक पूर्व शर्त है और, इसलिए, उपधारा (4) के प्रावधानों को इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि कुछ गवाहों की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट पर कर्तव्य लगाया जाए। तर्क यह है कि उपधारा (6) में खंड, अर्थात्, "जब उपधारा (4) में संदर्भित साक्ष्य लिया गया है" दोषमुक्ति का आदेश देने के लिए एक शर्त है। संदर्भ में खंड में क्रियाविशेषण "कब" एक समय बिंदु को दर्शाता है, न कि किसी पूर्ववर्ती स्थिति को। इस खंड का मतलब इससे अधिक कुछ नहीं है कि इसमें उल्लिखित घटनाओं के घटित होने के बाद उप-धारा (6) के तहत निर्वहन का आदेश दिया जा सकता है। दूसरे, दोनों खंड आवश्यक रूप से पहले के उप-अनुभागों के तहत संबंधित या उपयुक्त स्थितियों को संदर्भित करते हैं। यदि मजिस्ट्रेट ने कोई साक्ष्य नहीं लिया है तो पहला खंड लागू नहीं होगा। इसी तरह, उपधारा (7) में भी क्रियाविशेषण "कब" उस समय को दर्शाता है जब मजिस्ट्रेट सुपुर्दगी का आदेश दे सकता है। यदि साक्ष्य नहीं लिया गया है, और वह उप-धारा लागू नहीं होती है और मजिस्ट्रेट उप-धारा में निर्दिष्ट अन्य सामग्री पर सुपुर्दगी का आदेश देने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर, यदि उक्त दो उप-धाराओं को, जैसा भी मामला हो, दोषमुक्त करने या सुपुर्दगी का आदेश देने के लिए एक शर्त लगाने के रूप में समझा जाता है, तो उक्त दो उप-धाराएं सीधे तौर पर उप-धारा (4) के प्रावधानों के विरोध में आ जाएंगी। जब एक उपधारा स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने या न लेने का विवेकाधिकार प्रदान करती है, तो अन्य उपधाराएं इसे छीन लेती हैं। उपधारा की व्याख्या पर विवाद उत्पन्न करना स्वीकार्य नहीं है, जबकि वैकल्पिक व्याख्या द्वारा

तीनों उप-वर्गों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यदि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए स्वरूप को अपनाया जाता है, तो इससे एक विसंगति भी पैदा होगी कि मजिस्ट्रेट, हालांकि धारा 173 में संदर्भित दस्तावेज स्पष्ट रूप से अभियुक्त की निर्दोषता की घोषणा करते हैं, फिर भी उसे उप-धारा के प्रावधानों को संतुष्ट करने के लिए एक या अधिक गवाहों की जांच करनी पड़ेगी। वारंट मामलों के संबंध में संहिता की धारा 251ए पर भरोसा रखा गया है जिसके तहत मजिस्ट्रेट को धारा 173 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी जांच करने पर, जो मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, यदि वह आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है; लेकिन अगर उसकी राय है कि इस बात का आधार है कि आरोपी ने उसके खिलाफ कथित अपराध किया है, तो वह आरोपी के खिलाफ लिखित में आरोप विरचित करेगा। यदि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रावधान की तुलना धारा 207 ए से करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि यदि विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा इंगित दो प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट अंतर मिट जाएगा। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। यह दो धाराओं के तहत अलग-अलग प्रक्रियाओं को अलग करता है और विधानमंडल द्वारा प्रदान की गई शर्तों या सीमाओं को जोड़ना न्यायालय का क्षेत्र नहीं है।

माचेरला हनुमंत राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ([1958 एस.सी.आर. 396) में इस न्यायालय के फैसले से हम अपने विचार में दृढ हुए हैं। वहां विवाद का मुद्दा यह था कि क्या संशोधन अधिनियम XXVI/1955 द्वारा संहिता में जोड़ी गई धारा 207 और 207 ए ने संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस तर्क के समर्थन में कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, यह बताने की मांग की गई कि संहिता की धारा 207 ए के प्रावधान, संहिता के अध्याय XVIII के

अन्य प्रावधानों की तुलना में और इसके विपरीत, उस अध्याय के आगामी प्रावधानों में अन्य मामलों में निर्धारित प्रक्रिया की तुलना में पुलिस रिपोर्ट के तहत शुरू की गई कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों के लिए कम लाभप्रद स्थिति निर्धारित की गई है। इस न्यायालय ने माना कि प्रक्रियाओं में अंतर का समर्थन करने के लिए एक उचित वर्गीकरण था। सिन्हा जे., जैसा कि वह उस समय थे, जिन्होंने भेदभाव पर आधारित तर्क को पूरा करने के लिए न्यायालय के लिए बात की थी, उन्होंने नए खंड के दायरे पर विचार किया। ऐसा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 403 पर इस प्रकार टिप्पणी की:

> "तब मजिस्ट्रेट को घटना के चश्मदीद गवाहों के रूप में ऐसे गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने होते हैं, और उन्हें उसके सामने पेश किया जाता है। उसके पास न्याय के हित में, अभियोजन के ऐसे अन्य साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने की भी शक्ति है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, लेकिन वह किसी भी साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं है। बिना किसी साक्ष्य को दर्ज किए, लेकिन धारा 173 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और आरोपी व्यक्ति की जांच करने और पक्षों को सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को उसके कारणों को दर्ज करने के बाद आरोपमुक्त कर सकता है कि आरोपी को मुकदमे के लिए सुपुर्द करने का कोई आधार नहीं बनाया गया, जब तक कि वह अभियुक्त पर स्वयं मुक़दमा चलाने या उसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा मुक़दमे के लिए भेजने का निर्णय नहीं लेता। दूसरी ओर, यदि उसे लगता है कि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान दोषी ठहराया जाना चाहिए, तो उसे उस अपराध का खुलासा करते हुए

आरोप तय करना होगा जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है।"

तब विद्वान न्यायाधीश संहिता की धारा 208 के दायरे पर विचार करने के लिए आगे बढ़े। यह पाए जाने के बाद कि प्रक्रिया में स्पष्ट अंतर था, बॉम्बे के विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "विधानमंडल ने बहुत ही प्रासंगिक विचार के आधार पर सुपुर्दगी चरण में दो प्रकार की कार्यवाहियों के बीच एक स्पष्ट वर्गीकरण का प्रावधान किया है, अर्थात्, क्या किसी जिम्मेदार लोक सेवक द्वारा पिछली जांच की गई है या नहीं, जिसका कर्तव्य अपराध का पता लगाना और अपराधियों को त्वरित न्याय दिलाना है"। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि पृष्ठ 403 पर विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों को ओबिटर नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता हमसे यह मानने के लिए कहते हैं, कि धारा 207 ए के प्रावधानों के निर्माण के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि क्या वर्गीकरण उचित था या नहीं। यह मानते हुए कि उक्त टिप्पणियाँ ओबिटर हैं, तब भी, वे इस न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों की सुविचारित राय दर्ज करते हैं। हमने जो विचार व्यक्त किया है वह भी उक्त टिप्पणियों के अनुरूप है।

हमारा विचार अब निम्नलिखित प्रस्तावों में व्यक्त किया जा सकता है: (1) पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट केवल उन चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य लेने के लिए बाध्य है जो वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए हैं। (2) मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय है कि साक्ष्य लेना न्याय के हित में है, चाहे वह चश्मदीद गवाहों का हो या अन्य का, तो ऐसा करना उसका कर्तव्य है। (3) यदि मजिस्ट्रेट की राय यह नहीं है और यदि अभियोजन पक्ष ने किसी भी चश्मदीद गवाह की जांच नहीं की है, तो उसके पास संहिता की धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के

आधार पर आरोपी को रिहा करने या सत्र को सुपुर्द करने का अधिकार क्षेत्र है। (4) उपधारा (4) के तहत मजिस्ट्रेट का विवेक एक न्यायिक विवेक है और इसलिए, उचित मामलों में, जैसा भी मामला हो, दोषमुक्ति या सुपुर्दगी का आदेश, एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

मामले पर निष्कर्ष से पहले हम कुछ टिप्पणियाँ करना चाहेंगे। हमें ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जहां अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण चश्मदीदों से पूछताछ नहीं करता, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया से अभियुक्तों द्वारा उक्त गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संहिता की धारा 288 के तहत कोई ठोस साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। भले ही अभियोजन पक्ष यह जोखिम उठाता है, मजिस्ट्रेट धारा 207ए की उपधारा (4) के दूसरे भाग के तहत एक मजबूत न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा ताकि यह राय बनाई जा सके कि गवाहों की जांच की जानी चाहिए या नहीं और उस विवेक के किसी भी विकृत प्रयोग को हमेशा एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई मामला हो सकता है जहां मजिस्ट्रेट किसी मौखिक साक्ष्य की सहायता के बिना धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर निश्चित रूप से अपना मन बना सकता है और उस स्थिति में, जैसा भी मामला हो, आरोपी को दोषमुक्त करना या सुपुर्द करना उसके अधिकार में होगा। इस दृष्टि से इस विषय में अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि भले ही मजिस्ट्रेट ने बिना किसी साक्ष्य के किसी आरोपी को सुपुर्द करने में अवैध रूप से कार्य किया हो, उक्त अवैधता या तो संहिता की धारा 537 या उसकी किसी अन्य धारा द्वारा ठीक की जाती है।

परिणामस्वरूप, अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।